राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 1 ■ अंक 10 ■ मार्च 2018 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32

भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता

मिशन साहसी कार्यक्रम में छात्राओं के शौर्य का भव्य प्रदर्शन 10

Gender Perspective and Empowerment in India: Challenges and Constraints 21

75 फीसदी अनिवार्य उपस्थिति पर विरोध कितना सही? 29

परिषद् गतिविधियां

एग्रीवीजन कार्यशाला, उदयपुर के दौरान मंचासीन अतिथि एवं अभाविप के पदाधिकारीगण

दमण में भगिनी निवेदिता सार्धशती समारोह को संबोधित करते अभाविप के विशेष क्षेत्र संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 1, अंक 10
मार्च, 2018

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में

05 **भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता**
वास्तव में ईस्वी संवत् एक सांप्रदायिक कालगणना है। यह ईसाइयों द्वारा स्वीकृत कालगणना है, जैसे कि मुसलमान हिजरी...

संपादकीय	04
मिशन साहसी कार्यक्रम में छात्राओं के शौर्य का भव्य प्रदर्शन	10
एग्रीविजन कार्यशाला में उठी कृषि शिक्षा में सुधार की मांग	12
GENDER PERSPECTIVE AND EMPOWERMENT IN INDIA : CHALLENGES AND CONSTRAINTS	21
पटना विश्वविद्यालय समेत बिहार के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय में लहराया भगवा	24
भगिनी निवेदिता का योगदान अविस्मरणीय : खंडेलवाल	25
महिला सशक्तीकरण और अभाविप	26
अभाविप द्वारा आयोजित निशुल्क शिक्षा शिविर से गरीब छात्रों के उम्मीदों की लगे पंख	28
75 फीसदी अनिवार्य उपस्थिति पर विरोध कितना सही?	29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पिछले कुछ समय से खद-बदा रहा है। प्रशासन के प्रत्येक निर्णय के विरोध में तो प्रदर्शन होते ही हैं, देश भर में कहीं भी कुछ होने पर उसकी प्रतिक्रिया जेएनयू में अवश्य होती है, यदि उसे संघ-भाजपा या राष्ट्रवाद के विरोध में भुनाया जा सके। यही स्थिति उस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय संस्थानों की है जहां वाम दलों के विभिन्न अवतार सक्रिय हैं।

वस्तुतः इस प्रकार की गतिविधियों का शिक्षा अथवा उसके प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। देश भर में भारत विरोधी आंदोलन को जिस तरह से चुनौती मिल रही है उसने उन्हें भयभीत किया है। बंगाल और त्रिपुरा जैसे गढ़ टूटने के बाद, और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों पर कड़े प्रहार के बाद एक-दूसरे को समझौतावादी बताने वाले "सॉफ्ट वाम से लेकर रेडिकल वाम" तक अपना अस्तित्व बचाने के लिये एक साथ आने को विवश हुए हैं। जिन स्थानों पर अभी भी इनके समर्थकों की संख्या अधिक है वहां वे पूरी ताकत से हारती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं।

यह तो स्पष्ट है कि वामपंथी चिंतन में लोकतंत्र के लिये संघर्ष की बात केवल बहाना भर है। यह विचारधारा लोकतंत्र में न तो सिद्धांत रूप में विश्वास करती है और न ही जहां-जहां इनके हाथ में सत्ता आयी, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन ही किया। दुर्भाग्य की बात है कि अपने दलीय स्वार्थ के लिये अन्य राजनैतिक दलों ने भी इन ताकतों से हाथ मिला लिया। वहीं अपनी सांप्रदायिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर मानने वाले भी इनके साथ जुड़ गये। देश में एक राष्ट्रीयता विरोधी खेमा तैयार हो गया जो परस्पर भिन्न विचारधारा और मत के बावजूद राष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध एकजुट है।

उदाहरण के लिये, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक प्रमुख नेता को केवल इसलिये पार्टी से निलंबित कर दिया क्योंकि वह हाल में ही मेरठ में सम्पन्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सम्मेलन में दर्शक रूप में आमंत्रित थे। दूसरी घटना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है, जहां राष्ट्रपति श्री कोविंद के आठ साल पुराने एक कथित बयान को लेकर विश्वविद्यालय में आगमन पर उन्हें माफी मांगने अथवा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गयी। विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी ने स्थानीय विधायक, सांसद और संघ कार्यकर्ताओं को परिसर में प्रवेश न करने देने की भी घोषणा की। जानकारी हो कि एएमयू भी जेएनयू की तरह ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिसका सारा खर्च केन्द्र सरकार उठाती है।

भारतीय समाज में स्वीकृत मूल्यों, राष्ट्रीय एकात्मता के विचार, इस धरती से उत्पन्न दार्शनिक चिन्तन, सांस्कृतिक विरासत जैसे सभी बिन्दु, जो एक साधारण नागरिक के मन में अपने देश के प्रति गौरव जगाते हैं, इन कॉमरेडों और उनके राजनैतिक चट्टे-बट्टों के निशाने पर हैं। इस जुनून में वे इस सत्य को सामने पाकर भी आंखें मूंद ले रहे हैं कि इन्हीं गतिविधियों और सोच के कारण देश उन्हें नकार रहा है और वे निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राजनैतिक दल भी तात्कालिक लाभ के लिये जिस डूबते जहाज की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, वह उनके खिलाफ ही जायेगा।

भारत अब जाग रहा है और जो इसकी इस गौरव यात्रा में सहभागी होने को तैयार नही, वे सहानुभूति के पात्र हैं। किन्तु जो इसके विरोध में अपनी शक्ति झोंक रहे हैं, उनकी नियति दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है । वे इससे नजरें चुरा सकते हैं किन्तु इसे मिटा सकता उन के बूते की बात नहीं।

राष्ट्रविरोधी विचारधाराओं का प्रतिकार करने के साथ ही आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान की जानकारी भी विद्यार्थियों तक पहुंचे और तर्काधारित ज्ञान परम्परा से वे परिचित हो सकें। इसे ध्यान में रखते हुए चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होनेवाले भारतीय नवसंवत की वैज्ञानिकता को बताने वाला एक आलेख इस अंक में दिया है। अन्य स्थायी स्तंभों सहित यह अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

भारतीय नववर्ष की हार्दिक मंगलकामनाओं सहित,

आपका

संपादक

भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता

| रवि शंकर |

वास्तव में ईस्वी संवत् एक सांप्रदायिक कालगणना है। यह ईसाइयों द्वारा स्वीकृत कालगणना है, जैसे कि मुसलमान हिजरी संवत् मानते हैं और कुछ अन्य संप्रदाय उनके प्रवर्तकों के अनुसार संवत् स्वीकार करते हैं। यह देखना निश्चय ही आश्चर्यजनक ही है कि सत्य की आराधना करने वाले वैज्ञानिकों को कोई भी वैज्ञानिक घटना आधारित कालगणना नहीं मिली और वे भी इसी सांप्रदायिक कालगणना को अपनाए हुए हैं। इस पर भी यह अपराधबोध उन सभी के मन में अवश्य रहा होगा कि वे पूरे विश्व को एक प्रकार का धोखा दे रहे हैं और इसलिए अट्ठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इसका नाम बदलने की प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने इसे कॉमन एरा कहना प्रारंभ कर दिया।

एक जनवरी, 2018 ईस्वी संवत् बीत चुका है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत् 2086 आ रही है। जहाँ तक उत्सव मनाने की बात है, उत्सवधर्मी भारतीय दोनों ही अवसरों का लाभ उठाकर मौज-मस्ती कर लेते हैं। परंतु जब इतिहास और व्यवहार की बात आती है तो भारत की सरकार और बुद्धिजीवी, दोनों ही केवल और केवल ईस्वी संवत् का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा करने के लिए सरकारों को अधिक दोष नहीं दिया जा सकता है। आखिर सरकार अपने आप में कोई बुद्धि और विद्या की नियामक संस्था नहीं होती, परंतु देश के बुद्धिजीवियों को इसके लिए सरासर दोषी माना जाना चाहिए कि उन्होंने पूरे देश पर एक मिथ्या, अवैज्ञानिक और तर्करहित कालगणना केवल इसलिए थोप रखी है कि यूरोपीय और अमेरिका, आस्ट्रेलिया सरीखे नवयूरोप के लोग इसे ही मानते हैं। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि भारतीय नवसंवत् के स्वागत के इस अवसर पर कालगणना पर विचार करना समीचीन होगा।

आज का युग विज्ञान का युग कहा और माना जाता है। आज समस्त विश्व की सारी चीजें विज्ञान से ही निर्धारित होती हैं। विज्ञान की बात करें तो इसके लिए

भी एक सुनिश्चित सीमा बांध दी गई है। आज विज्ञान का अर्थ होता है यूरोपीय तथा नवयूरोपीय देशों द्वारा विकसित और स्वीकृत विज्ञान। हालांकि यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है, परंतु इसके कारण ही भारतीय ज्योतिष को अंधविश्वास मान लिया जाता है और एक नितांत काल्पनिक तथा अशुद्ध कालगणना को वैज्ञानिक कह दिया जाता है। आधुनिक यूरोपीय विज्ञान के अंधविश्वास में फंसे लोगों को बुद्धिजीवी कहना भी हालांकि एक प्रकार का बौद्धिक व्यभिचार ही होगा, फिर भी आवश्यक है उनके द्वारा फैलाए जा रहे इस अंधविश्वास का खंडन उनके ही तर्कों तथा तथ्यों से किया जाए। इसलिए भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता को स्थापित करने से पहले हम यह देखते हैं कि वर्तमान में प्रचलित कालगणना के आधार क्या हैं और वे आधार कितने वैज्ञानिक हैं।

सबसे पहली बात ईस्वी संवत् की है। आज इसे कॉमन एरा यानी कि सामान्य युग कहा जाने लगा है, परंतु इससे पहले इसे ईसा पूर्व तथा ईस्वी संवत् के रूप में ही लिखा-पढ़ा जाता था। ईसा पूर्व और ईस्वी संवत् का सीधा अर्थ है कि ईसा के पहले और ईसा के बाद का काल। प्रश्न उठता है कि क्या ईसाई मजहब के प्रवर्तक हजरत ईसा एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं? यदि विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को देखें तो उनमें कहीं भी हजरत ईसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं दिखाए जाते। प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिक इतिहासलेखन के नाम पर भारत के समस्त ग्रंथों और परंपराओं को मिथकीय मानने वाली बौद्धिक जमात एक मिथकीय व्यक्तित्व के आधार पर कालगणना क्यों पढ़ और पढ़ा रही है? क्या देश की जनता को इन महान विद्वान कहे और माने जाने वाले प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों से यह पूछने का हक नहीं है कि भारत के कण-कण में बसे श्रीराम को मिथकीय चरित्र मानने वाले ये लोग ईसा के आधार पर कालगणना भारत के बच्चों को पढ़ाये जाने का विरोध क्यों नहीं कर पाए?

वास्तव में ईस्वी संवत् एक सांप्रदायिक कालगणना है। यह ईसाइयों द्वारा स्वीकृत कालगणना है, जैसे कि मुसलमान हिजरी संवत् मानते हैं और कुछ अन्य संप्रदाय उनके प्रवर्तकों के अनुसार संवत् स्वीकार करते हैं। यह देखना निश्चय ही आश्चर्यजनक ही है कि सत्य की आराधना करने वाले वैज्ञानिकों को कोई भी वैज्ञानिक घटना आधारित कालगणना नहीं मिली और वे भी इसी सांप्रदायिक कालगणना को अपनाए हुए हैं। इस पर भी यह अपराधबोध उन सभी के मन में अवश्य रहा होगा कि वे पूरे विश्व को एक प्रकार का धोखा दे रहे हैं और इसलिए अट्ठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इसका नाम बदलने की प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने इसे कॉमन एरा कहना प्रारंभ कर दिया। इससे ईसा पूर्व की अंग्रेजी बिफोर क्राइस्ट के छोटे रूप को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी केवल उसमें एक ई अक्षर जोड़ दिया गया और इस प्रकार बीसी बन गया बीसीई सामान्य युग से पूर्व। ए.डी. यानी एनस डोमिनी यानी इयर ऑफ लार्ड यानी ईस्वी सन् को कॉमन एरा यानी सामान्य युग कहा गया और इस तरह यह बन गया सीई। वर्ष 2002 में इंग्लैंड और उसके पड़ोसी द्वीप वेल्श ने इसे आधिकारिक रूप से शिक्षा प्रणाली में शामिल कर दिया। इसके बाद भी नौ वर्षों तक विश्व इसे अपना नहीं पाया। वर्ष 2011 में अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने भी इसे अधिकृत रूप से लागू कर दिया।

चूंकि यूरोपीय और नवयूरोपीय सभी देश ईसाईमत प्रधान देश हैं, इसलिए उनके लिए स्वाभाविक ही था कि वे अपनी सांप्रदायिक दिखने वाली गणना को एक सेकुलर छवि प्रदान करने की कोशिश करते। परंतु दुर्भाग्यवश भारत के किसी भी बुद्धिजीवी ने इस पर प्रश्न ख़ड़ा नहीं किया, बल्कि वे इसकी अंधी नकल में जुट गए। भारतीय इतिहासलेखक भी बीसी और एडी के स्थान पर बीसीई तथा सीई का प्रयोग करने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि बीसी और एडी लिखने वालों को इतिहासज्ञान में पिछड़ा और अल्पज्ञ भी माना और बताया जाने लगा। भारतीय इतिहासकारों को यह पूछना चाहिए था कि सीई यानी कि कॉमन एरा में कॉमन प्वाइंट यानी कि साझा बिंदु क्या है? यदि यह साझा बिंदु ईसा का जन्म ही है तो फिर बीसी और एडी में क्या बुराई है? यदि यह कोई अन्य ऐतिहासिक या खगोलीय घटना है तो फिर वे बताएं कि वह घटना क्या है?

ईसा पूर्व तथा ईस्वी संवत् तथा कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा की सांप्रदायिकता, अनैतिहासिकत्व तथा अवैज्ञानिकता को समझने के बाद अब हम यह देखते हैं कि मानव इतिहास को जो काल विभाजन आज देश के कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वह कितना वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण है। वर्तमान में मानव के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया

जाता है – पुरा पाषाणयुग, पाषाणयुग, कांस्ययुग और लौहयुग। इसका कालखंड भी कुछ-कुछ निर्धारित है। कुछ-कुछ इसलिए कि ये कालखंड हैं और इसलिए इनकी सीमा ही आंकी जा सकती है, निश्चित काल नहीं (कृपया चार्ट देखें)। उदाहरण के लिए लौह युग का काल 1000 वर्ष ईसा पूर्व का माना जाता है। इस युगगणना को कुछ इस प्रकार निर्धारित कर दिया गया है कि इसमें का विज्ञान गायब हो गया है और इसमें केवल अंधविश्वास शेष बच गया है। यानी आप इस पर प्रश्न खड़े नहीं करते, बस इसे मान लेते हैं और इसके आधार पर ही नए मिलने वाले तथ्यों की व्याख्या करते हैं।

इस अंधविश्वास को समझना हो तो एक उदाहरण देख सकते हैं। लौह युग को 1000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है यानी ईसा के 1000 वर्ष से पहले मानव को लोहे का प्रयोग ज्ञात नहीं था। अब इतिहास का एक तथ्य देखें। कालीबंगा, राजस्थान में 3000 वर्ष ईसा पूर्व का एक जुता हुआ खेत खुदाई में मिला है। यह खेत बिल्कुल आधुनिक तरीके से दो फसलों की मिश्रित खेती के लिए जुता हुआ है। अब खेत की जुताई बिना हल के नहीं की जा सकती और हल बिना लोहे के नहीं बन सकता। वस्तुतः लकड़ी का कोई भी सामान बिना लोहे के औजारों की सहायता के नहीं बन सकता। परंतु चूंकि आज के विज्ञान के अंधविश्वास में 1000 वर्ष ईसा पूर्व से पहले लोहे के औजार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इतने महत्वपूर्ण प्रमाण की उपेक्षा कर दी जाती है और कहा जाता है कि कांसे से ही यह सब कुछ किया गया होगा।

बहरहाल, भले ही भारत में आज इन युगों के विभाजन को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो, फिर भी इन युगों के विभाजन का प्रतिपादन करने वाले विद्वान भी इसकी व्यर्थता को नकार नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए हिस्ट्री ऑफ एनशिएंट सिविलीजेशन में चार्ल्स साइनोवोस लिखते हैं, "एक और उसी देश के लोगों ने क्रमशः अनगढ़ पत्थरों, तराशे हुए पत्थरों, कांसे तथा लोहे का प्रयोग करना सीखा। परंतु सभी देश एक ही समय में एक साथ एक ही युग में नहीं रहे। मिश्र ने तभी लोहे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया जब ग्रीक कांस्ययुग में ही जी रहे थे और डेनमार्क के बर्बर लोग पत्थरों का ही प्रयोग कर रहे थे। अमेरिका में तराशे गए पत्थरों का युग (नूतन पाषाण युग) यूरोपियों के वहाँ जाने के बाद समाप्त हुआ। हमारे अपने काल में अभी भी आस्ट्रेलिया के असभ्य कबीले अनगढ़ पत्थरों के काल में ही रह रहे हैं। ...इस प्रकार ये चार युग मानवता की यात्रा के कालखंडों को प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि हरेक देश में ये सभ्यता के विकास की कहानी कहते हैं।"

> ईसा पूर्व तथा ईस्वी संवत् तथा कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा की सांप्रदायिकता, अनैतिहासिकत्व तथा अवैज्ञानिकता को समझने के बाद अब हम यह देखते हैं कि मानव इतिहास को जो काल विभाजन आज देश के कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वह कितना वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण है। वर्तमान में मानव के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया जाता है – पुरा पाषाणयुग, पाषाणयुग, कांस्ययुग और लौहयुग।

प्रश्न उठता है कि यदि यह बात सच है तो किस आधार पर अपने देश में बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि लौह युग केवल हजार वर्ष ईसापूर्व में प्रारंभ हुआ? फिर हम पूरी दुनिया के इतिहास को नियोलिथिक, पैलियोलिथिक आदि युगों में क्यों बांट देते हैं? यह कालखंड तो हरेक देश का अलग-अलग होना था। इसके लिए हरेक देश के इतिहास की अलग-अलग पड़ताल करनी थी। उदाहरण के लिए भारत की बात करें तो यहाँ वेदों में लोहे का स्पष्ट उल्लेख है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार भी वेद तो कम से कम 4-5 हजार वर्ष पुराने हैं। स्पष्ट है कि भारत का लौहयुग कम से कम 4-5 हजार वर्ष पुराना होना ही चाहिए। ऐसे में शेष युग तो और भी पीछे चले जाएंगे। इसमें अभी एक और समस्या है।

समस्या यह है कि विश्व के सभी देशों में नूतन पाषाण युग के बाद कांस्य युग नहीं आया। प्राचीन भारत के इतिहासकारों में एक प्रमुख नाम स्व. राधाकुमुद मुखर्जी अपनी पुस्तक हिंदू सभ्यता में लिखते हैं, "भारतवर्ष में अन्य देशों की भांति विकास-क्रम की ये सारी अवस्थाएं होती हैं। केवल कांस्य-युग के स्थान पर (कुछ प्रदेशों को छोड़ कर) ताम्र-युग से मिलती संस्कृति यहाँ हुई।" वे यह भी लिखते हैं कि "पूर्व-प्रस्तर के अवशेष यहाँ कम ही हैं।" इसका अर्थ यह है कि भारत में पत्थरों के औजारों का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ। एक और

मजेदार बात यह है कि पाषाण युग में भी भारत में लोहे के औजार मिल रहे हैं। राधाकुमुद मुखर्जी लिखते हैं, "दक्षिण भारत में कई स्थानों पर नव-प्रस्तर-युग की बस्तियां तथा उनके औजारों को गढ़ने की कर्मशालाओं के स्थान पाए गए हैं। ज्ञात होता है कि वे लोग अपने औजारों को कड़ी चट्टानों पर बनाई हुई घाइयों में घिसते और माडते थे। 10 से 14 इंच तक लम्बी और दो इंच गहरी घाइयां पाई गई हैं। इन बस्तियों में चाक के बढ़िया बर्तन बहुतायत में मिले हैं, लम्बे ताबूत मिले हैं, जिनके साथ कभी-कभी लोहे के औजार भी पाए गए हैं। पत्थर की शिलाओं से निर्मित समाधियां या स्थाणु-संज्ञक निखात स्थान (मैगेलिथिक टोम्ब) मद्रास, बम्बई, मैसूर और हैदराबाद (दक्षिण) राज्य में बहुतायत में मिले हैं, परंतु उनमें प्राप्त लोहे के औजारों से वे नव-प्रस्तर-युग की ज्ञात होती हैं। ...पाषाण-युग के बाद दक्षिण भारत में लौह-युग और उत्तर भारत में ताम्र-युग आया।"

उपरोक्त विवरण साफ कर देता है कि मानव सभ्यता का पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का विभाजन भारत पर लागू नहीं होता। जिसे यूरोपीय पाषाण युग कह रहे हैं, भारत में उस काल में भी लोहे के औजार मिल रहे हैं और भारत में तो कांस्य युग आ ही नहीं रहा है। यहाँ पहले लौह तथा ताम्र युग आ रहा है। हालांकि यदि भारतीय शास्त्रों के मत को देखें तो यह सारा युग विभाजन मूर्खतापूर्ण ही जान पड़ता है। महाभारत जोकि आज से पाँच हजार वर्ष पहले की घटना है और जिसकी ऐतिहासिकता को नकारने का कोई कारण नहीं है, में लोहे का पर्याप्त से अधिक प्रयोग पाया जाता है। पाँच हजार वर्ष पूर्व यूरोप का इतिहास प्रारंभ ही हो रहा था। वहाँ तो इस समय मनुष्य पूर्वपाषाण युग में जी रहा था। फिर आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार रामायण की घटना आज से 8-9 हजार वर्ष पहले हुई। रामायण में भी लोहे के प्रयोग के भरपूर वर्णन हैं। ऐसे में भारत में लौह युग तो और पहले का मानना पड़ेगा। इस काल में यूरोप में मानव के इतिहास का प्रारंभ भी नहीं होता। वहाँ डार्विन के मतानुसार अभी बंदर ही उछल-कूद कर रहे थे। यदि भारतीय मतों को मानें तो रामायण का काल और पीछे जाएगा और रामायण को हमारे इतिहास में काफी बाद की घटना है, उससे पहले लाखों वर्षों का इतिहास घटा है जिसमें लोहे के प्रयोग पर्याप्त हैं।

इस सारे विवरण को पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि मानव सभ्यता के विकास को आज जिन चार कालखंडों में बाँटा जाता है, वे न केवल मिथ्या हैं, बल्कि भ्रामक भी हैं। उन्हें ये चार कालखंड इसलिए बनाने पड़ें ताकि वे पूरी दुनिया के इतिहास को यूरोप के इतिहास के सांचे में ढाल सकें। वे यह बता सकें कि यूरोप शेष दुनिया से थोड़ा बहुत ही पीछे था, और उसने पिछले 3-4 सौ वर्षों में पूरी दुनिया को पीछे कर दिया है। सचाई यह है कि दुनिया का इतिहास इन चार कालखंडों में नहीं बाँटा जा सकता। प्रख्यात भूगर्भशास्त्री चार्ल्स हैपगुड अपनी पुस्तक मैप्स ऑफ एनशिएंट सीकिंग्स में लिखते हैं, "पाषाण युग की संस्कृति, नवपाषाण युग, कांस्य युग, और लौह युग के क्रमबद्ध स्तरों से होती हुई मानवी सभ्यता के सरल एकरैखिक विकास की संकल्पना को त्याग दिया जाना चाहिए। आज हम पाते हैं कि दुनिया के सभी महादेशों में आदिम संस्कृतियां विकसित आधुनिक समाज के साथ रहती हैं – आस्ट्रेलिया के बुशमेन, दक्षिण अफ्रीका के बुशमेन, दक्षिण अमेरिका और गुएना के सच्चे आदिम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ कबीलाई लोग आदि। हमें अब यह मान लेना चाहिए कि आज से 20 हजार वर्ष पहले जब यूरोप में पाषाण युगीन लोग रह रहे थे, पृथिवी के अन्य हिस्सों में उससे कहीं अधिक विकसित संस्कृतियां उपस्थित थीं और आज हमारे पास जो कुछ भी है, उसका एक हिस्सा उनकी ही विरासत है जोकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गईं।"

प्रसिद्ध अंतरिक्षविज्ञानी डॉ. ओमप्रकाश पांडेय कहते हैं, "इस तरह का कालविभाजन वास्तव में समय के एकरैखिक विकास की यहूदी-ईसाई संकल्पना की उपज है। भारतीय संकल्पना में काल की गति चक्रीय है, एकरैखिक नहीं और इसलिए भारतीय संकल्पना समय की अधिक बड़ी दूरी को माप सकती है।" इसलिए भारतीय युग गणना लाखों-करोड़ों वर्षों की बात करती है, जो बाइबिल के ईसा की कालगणना से बंधे यूरोपीयों को समझ में नहीं आ पाती। चार्ल्स हैपगुड सरीखे जो यूरोपीय इस बाधा से मुक्त हो गए हैं, वे भी मानव सभ्यता का इतिहास लाखों वर्षों का मानने लगे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि भारत की जिस करोड़ों तथा अरबों वर्षों की गणना को यूरोपीय मिथक मान कर खारिज कर देते हैं, आज का भूगर्भशास्त्र भी लगभग उसी प्रकार की करोड़ों तथा अरबों वर्षों की गणना करने लगा है।

आज की भूगर्भशास्त्रीय कालगणना को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भारतीय कालगणना के मापकों को ग्रीक नाम देकर अपना रखा है। अंतर केवल उनकी थोड़ी बहुत अज्ञानता और कालगणना के अशुद्ध तरीकों के कारण अंकों का ही है। एक तुलनात्मक विवरण देखें। भूगर्भशास्त्र में काल की सबसे पुरानी माप हैडियन की है जो कि आज से 4.6 से लेकर 4.0 अरब वर्ष पहले का है। भूगर्भशास्त्रियों का मत है कि इतने समय पूर्व सृष्टि का आरंभ हुआ। अब इसकी तुलना करें हमारे एक ब्राह्म वर्ष से।

भारतीय मतानुसार ब्रह्मा का एक दिन-रात यानी कि चौबीस घंटे मानवीय गणना में 4.32 अरब वर्षों का होता है। इसे हम एक कल्प भी कहते हैं। कल्प के प्रारंभ में सृष्टि का आरंभ माना जाता है। भूगर्भशास्त्रियों ने इस पूरे कालखंड को दो भागों जिसे वे इयॉन कहते हैं, में तो बाँटा है, परंतु वे दो भाग समान नहीं हैं। पहला विभाजन है प्रिकैम्बियन इयॉन जो कि 4.6 अरब वर्ष से 54.2 करोड़ वर्ष पूर्व तक का है और दूसरा है फैनेरोजोइक इयॉन जोकि 54.2 करोड़ वर्ष से लेकर आज तक का काल है। दोनों इयॉन को एरा में बाँटा गया है। प्रिकैम्बियन इयॉन में दो एरा हैं। पहला आर्कियन एरा चार अरब वर्ष पूर्व से लेकर 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक का है और दूसरा प्रोटेरोजोइक एरा 2.5 अरब वर्ष से लेकर 54.2 करोड़ वर्ष पूर्व तक का है। यह विभाजन भी समान नहीं है। एरा को आगे पीरियड में बाँटा गया है। आर्कियन एरा में चार पीरियड और प्रोटेरोजोइक एरा में तीन पीरियड हैं।

फैनेरोजोइक इयॉन को तीन एरा में बाँटा गया है। पहला, पैलियोजोइक एरा 54.2 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 25.1 करोड़ वर्ष पूर्व तक का, दूसरा, मेसोजोइक एरा 25.1 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का और तीसरा, सेनोजोइक एरा 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर आज तक का। इन तीनों एरा को भी आगे पीरियड में बाँटा गया है। पीरियड को इपोक में और फिर उन्हें एज में बाँटा गया है। ये सारे विभाजन बड़े ही असमान और अस्त-व्यस्त हैं। इनमें कोई क्रमबद्धता नहीं दिखती।

इस कालविभाजनों के लिए भूगर्भशास्त्रियों ने जो प्रमाण दिए हैं, उनका आड़ोलन करने से हमें इस कालविभाजन की प्रामाणिकता और सत्यता का पता चलता है। भूगर्भशास्त्री विभिन्न चट्टानों के अध्ययन और उनके काल के रासायनिक निर्धारण से यह कालविभाजन करते हैं। इस कालविभाजन में सबसे बड़ी खामी यही है। चट्टानों की आयु से सृष्टि के चक्र को समझना असंभव बात है। सृष्टि के चक्र में जल-प्लावन, बर्फयुग जैसी अनेक प्रकार की छोटी-मोटी घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं जो चट्टानों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं जबकि भूगर्भशास्त्री यह मान कर कालनिर्णय करते हैं कि प्रकृति भूगर्भशास्त्रीय प्रक्रियाएं प्रारंभ से लेकर आज तक गति और प्रमाण में समान दर से होती रही हैं। यह सिद्धांत वर्ष 1795 में जेम्स हट्टन ने दिया था जिसे थियोरी ऑफ यूनिफार्मिटी यानी समानता का सिद्धांत कहते हैं। यही सिद्धांत आज तक मान्य है और इसके आधार पर ही सारी भूगर्भशास्त्रीय कालगणना की जाती है।

चूंकि यह एक मानवीय गणना की क्षमता से परे लंबे कालखंड की बात है, इसलिए इसमें हमें कुछ चीजें मान कर ही चलनी होती हैं। परंतु यह कहना कहीं से भी ठीक नहीं है कि प्राकृतिक घटनाएं प्रारंभ से लेकर आज तक हमेशा एक ही गति और प्रमाण में होती रही हैं। यह संभव नहीं है। पृथिवी पर ताप और दाब जब हमेशा एक समान नहीं रहा है तो फिर प्रक्रियाओं की गति एक समान कैसे हो सकती है? इसलिए भूगर्भशास्त्र की ये सारी गणनाएं वस्तुतः एक मिथ्या सिद्धांत पर टिकी हैं।

अब यदि हम इसकी तुलना करें भारतीय कालगणना से तो हमें ध्यान में आता है कि भारतीय गणनाएं आकाशीय नक्षत्रों पर आधारित हैं। आकाशीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन कभी भी पृथ्वी की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि इसके उलट आकाशीय स्थितियों पर ही पृथ्वी की परिस्थितियां निर्भर करती हैं। स्वाभाविक ही है कि पृथिवी की कालगणना करने के लिए आकाश एक अधिक स्थिर और प्रामाणिक आधार है। इसलिए भारतीय ज्योतिष ने आकाशीय नक्षत्रीय गणना को ही प्रमाण माना और उसके आधार पर गणनाएं कीं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि भारतीय कालगणना न केवल वैज्ञानिक है, बल्कि वह अधिक ऐतिहासिक, प्रामाणिक और सेकुलर भी है। भारतीय इतिहासकारों को न केवल स्वयं इसे अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें विश्वपटल पर इसकी स्वीकार्यता के लिए संघर्ष भी करना चाहिए। ■

(लेखक भारतीय धरोहर पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं।)

मिशन साहसी कार्यक्रम में छात्राओं के शौर्य का भव्य प्रदर्शन

भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं का विशिष्ट स्थान रहा है, इक्सवीं सदी में महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, इसके बावजूद महिला सुरक्षा का विषय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे समय में छात्राओं के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा छात्राओं को निर्भय बनाने के लिए 'मिशन साहसी' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुंबई के मेरीन ड्राइव में किया गया, जहां पर एक साथ सात हजार से अधिक छात्राओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया।

क्या है मिशन साहसी?

अभाविप की मानें तो 'मिशन साहसी' - निर्भयता के निर्माण की भावना का परिचायक है। अभाविप, विद्यार्थी निधि, ग्रैंडमास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज के कुशल मार्गदर्शन में शिफूजी प्रहार मिशन के साथ अपनी इसी भावना को वास्तविकता में परिवर्तित कर रही है। मिशन साहसी एक ऐसा कदम है जो महिलाओं पर हो रहे शारीरिक हमलों के भय को जड़ से उखाड़ने के क्रम में आवश्यक आत्म विश्वास को जन्म देता है। इसका उद्देश्य समाज में महिलाओं के हितों से जुड़े विषयों के प्रति 'चलता है' जैसे रवैयों को ख़त्म करना है। परिषद् का मानना है कि महिलाओं में स्वयं की सुरक्षा करने की ऐसी विशेषता हो , जिससे किसी भी विषम परिस्थिति में उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न पड़े ।

यह मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों एवं सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा 14 से 25 आयु वर्ग की महिलाओं को आत्म रक्षा

का प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम है। मिशन साहसी को महिलाओं द्वारा दैनिक दिनचर्या में धमकियों का सामना करना, सूनसान सड़क एवं खाली ट्रेन में महिलाओं के अकेले होने जैसी स्थितियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अनुकूलित किया गया है। मिशन साहसी के प्रथम प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 8 फरवरी,2018 को ठाकुर महाविद्यालय (कांदिवली, मुंबई) में हुई, जिसमें लगभग 3000 से अधिक छात्राओं ने लिया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मुंबई के चार अन्य सुदूर स्थानों (के. जे. सोमैया महाविद्यालय - विद्याविहार , बीपीसीए प्रांगण – वडाला, मुंबई स्कूल एसोसिएशन ग्राउंड - सीएसटी , एसएनडीटी कैम्पस - जुहू) में प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई और महानगर मुंबई के कई महाविद्यालयों से आई हुईं छात्राओं को अपेक्षित कौशल प्रदान किया गया।

6 मार्च 2018 को मुंबई में सात हजार से अधिक युवतियों द्वारा प्राप्त कौशल का भव्य प्रदर्शन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्ज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई , उसके बाद संयोजिका प्रेरणा पवार द्वारा मिशन साहसी के पीछे छिपे विचारों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवन्द्र फडनवीस ने कहा - "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के सद्प्रयासों द्वारा छात्राओं को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जिस 'मिशन साहसी' कार्यक्रम का शुभारम्भ मुंबई में हुआ है, वह अपने आप में अत्यंत ही सराहनीय है, इसे महाराष्ट्र के कोने - कोने में व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि कुशल प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राएं सशक्त हो सकें । इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र में व्यापक स्तर पर आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर संभव मदद करेगी।।"

प्रदर्शन के द्वितीय चरण के दौरान छात्राओं ने ज्यादातर साथ रहने वाली वस्तुओं यथा - आई कार्ड, पेन / पेन्सिल का उपयोग करते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ छात्राओं ने अपने अनुभवों को साझा किया जो उन्होंने प्रशिक्षण के समय महसूस किया था। तत्पश्चात अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि - "अभाविप की छात्राएं अब विषम परिस्थितियों में असहाय की स्थिति में खड़ी नहीं रहेंगी, अपितु आगे बढ़कर अब प्रतिकार करते हुए करारा जवाब देंगी।। "

वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस भव्य प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि - " इतनी विशाल संख्या में अपनी बहनों - बेटियों द्वारा शौर्य प्रदर्शन देखते हुए मुझमें एक नवीन हिम्मत आ गई है। निश्चित रूप से मिशन साहसी एक बहुत ही अच्छा कदम है।" उसके बाद ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज ने मिशन साहसी के बारे में कहा कि - " जो एक छोटी सी चर्चा से शुरू हुई थी, वो चिंगारी आज बारूद से लगकर ज्वालामुखी में बदल चुकी है। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर जी ने अपने प्रखर विचारों को साझा करते हुए कहा कि – " छात्राओं के अन्दर निहित शक्ति को प्रशिक्षण के माध्यम से बाहर लाना ही मिशन साहसी का उद्देश्य है ।" ■

एग्रीविजन कार्यशाला में उठी कृषि शिक्षा में सुधार की मांग

भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन कृषि के प्रति लोगों का रूझान दिनोंदिन कम होता जा रहा है, जो देश के लिए घातक साबित हो सकता है। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभाविप के प्रकल्प एग्रीविजन द्वारा देशभर में कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिससे युवाओं में कृषि के प्रति रूचि पैदा हो तथा वे कृषि को रोजगार के रूप में अपनायें। इस कड़ी में बीते फरवरी माह में राजस्थान के उदयपुर में एक कृषि कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें देशभर के कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधार्थी एवं कृषि विश्वविद्यालय के छात्र एवं शिक्षकों ने भाग लिया। यह कार्यशाला उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में "कृषि शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की संभावना" विषय पर आयोजित थी। कार्यशाला में छात्रों ने एक स्वर में कृषि शिक्षा में सुधार की मांग की।

अभाविप के राष्ट्रीय सह - संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को कृषि के प्रति अपनी भागीदारी तय कर इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल चिकित्सकों की तरह कृषि अध्यापकों की सेवा पांच वर्ष के लिए किसान के साथ गांव में की जानी चाहिए ताकि वे धरातल पर कृषि की स्थिति के बारे में जान सके। राजस्थान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में 38 प्रतिशत सिंचित तथा 22 प्रतिशत वर्षा आधारित खेती होती है । इसलिए हमें कृषको को बागवानी करने के प्रति जागरूक करना होगा। वहीं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. यू. एस. शर्मा ने कृषको की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक प्रो ए. के. मेहता ने कृषि अभियांत्रिकी के महत्व के बारे में उपस्थित छात्रों को बताया ।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक प्रो एस. के. शर्मा ने कृषको की आय बढाने के लिए पुनः जैविक खेती की ओर लौटने

की बात की साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा जैविक कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया एवं उन्होंने रासायनिक कृषि से हो रही हानि तथा जैविक कृषि से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अंतिम सत्र में अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेन्द्र नाइक ने कृषि विद्यार्थियों की समस्या के बारे में चर्चा की। उन्होंने इन समस्याओं को दूर करने के बारे में सुझाव भी दिए साथ ही कृषि शिक्षा में महिलाओ की भागीदारी बढ़ाने की बात की। कार्यशाला को अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद पालिवाल एवं उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री नवीन शर्मा ने संबोधित किया।

एग्रीविजन कार्यशाला में अभाविप ने सरकार से कृषि शिक्षा में सुधार के लिए निजी संस्थानों द्वारा दी जा रही स्तरहीन शिक्षा पर अंकुश लगाने, कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर शिक्षकों को बहाल करने, शोध छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने, नियामक आयोग का गठन करने, पंचायत स्तर पर कृषि संकाय खोलने, कृषि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग की। ■

प्रांतीय अधिवेशन

केरल के 33 वें प्रांतीय अधिवेशन में अभाविप के राष्ट्रीय सह–संगठन जी. लक्ष्मण को सम्मानित करते स्वागत समिति अध्यक्ष विश्वरूपाणी

केरल प्रांतीय अधिवेशन के दौरान शोभा यात्रा निकालते अभाविप कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

तमिलनाडू के 23 वें प्रांतीय अधिवेशन के दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन करते अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. सुबैय्या व अन्य

तमिलनाडु प्रांतीय अधिवेशन में निकाली गई भव्य शोभायात्रा

प्रांतीय अधिवेशन

दीप प्रज्ज्वलित कर कर्नाटक प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन करते अतिथि एवं अभाविप के पदाधिकारीगण

कर्नाटक प्रांतीय अधिवेशन में शोभा यात्रा के दौरान उत्साह में अभाविप कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

ईशान्य प्रदेश के 20 वें प्रांतीय अधिवेशन के दौरान मंचासीन अभाविप पदाधिकारी

ईशान्य प्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान शोभायात्रा का नेतृत्व करतीं छात्रा कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

हरियाणा प्रांत के 49 वें प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन करते राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद मराठे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री एवं अभाविप के अन्य पदाधिकारी

हरियाणा प्रांतीय अधिवेशन के दौरान मंचासीन अभाविप के पदाधिकारीगण

प्रांतीय अधिवेशन

झारखंड के 18 वें प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन करते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, साथ में हैं शिक्षा मंत्री नीरा यादव, अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे व अन्य

प्रांतीय अधिवेशन के दौरान मंचासीन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार व अन्य

प्रांतीय अधिवेशन

कानपुर प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर भाजपा संगठन मंत्री(ऊ.प्र.) सुनील बंसल, स्वागत समिति अध्यक्ष जे.के. सिंह, प्रांत अध्यक्ष अनुप सिंह व अन्य

कानपुर प्रांतीय अधिवेशन के दौरान सभागार में अभाविप पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता

प्रांतीय अधिवेशन

महाकौशल प्रांतीय अधिवेशन के दौरान प्रांत कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यगण

महाकौशल प्रांत के प्रांतीय अधिवेशन में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा

Gender Perspective and Empowerment in India: Challenges and Constraints

"Women represent 50% of the total world population, they perform two-third of all working hours, receive one-tenth of the worlds income and own less than one percent of world property."

Dr. Shreeya Bakshi

Women hold the key to long lasting social changes in the communities. They constitute half of the world's population and if half of the population remains powerless, it leads to devaluing women and by devaluing women, men are not only dehumanizing one half of the human race but actually alienating themselves. Therefore, empowering women becomes essential. Empowerment, particularly women's empowerment, is defined as the process- and the result of the process- whereby the powerless or less powerful gain greater access and control over material and knowledge resources and challenge the ideology of discrimination and subordination which justify this unequal distribution. In simple words, Women Empowerment refers to increasing the spiritual, political, social or economic strength of Women. Women empowerment as a perspective of gender equity is a recent concept of 1990's which shot in to prominence in Beijing Conference in 1995.

As far India is concerned, the principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favour of women. The India Constitution tried to promote equal rights through the instrument of law. Despite the wide ranging protective legislations, women, in India, continue to face a great deal of discrimination in public and private life. Therefore, Empowerment became one of the key factors in determining the success of development in the status and position of women in the society.

Since centuries, women have been relegated to the subordinate position to men. In Vedic Period, women enjoyed equal status and rights as that of men, but in the medieval period and after that, the status of women degraded as she was excluded from education, land and property rights and was relegated to household tasks only. During the 19th and 20th century, socio-religious reform movements spread all over the India and various social reformers like: Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Dayanand Saraswati, Dr. BR Ambedkar, Mahatama Gandhi, Jotiba Rao Phule and many more fought for the unequal status of women. They took up the issues like: education of women, Widow remarriage, prohibition of Child marriage and so on.

All of them placed faith in law's ability to deliver social change. Social reformers sought to enact protective legislations to prohibit evil perpetrated on women. But their discourse was heavily embedded within familialism. In the immediate post-independence period, the campaign for both constitutional rights and Hindu Code Bill came to focus on formal equality. Women were easily allowed to enter

public sphere but when it came to equality in the private sphere there was a storm of resistance from the traditionalist force. Laws can be effective only if backed by strong public opinion. It is therefore essential that social legislation must be widely published and public opinion properly educated with a view to ensure a reasonable and willing acceptance by the society.

The Hindu woman does not have an independent identity; her identity is wholly defined by her relationship to others. An ancient law, as given by Manu says: "In childhood, a female must be subjected to her father, in youth her husband, when her lord is dead to her sons. A woman must never be independent." Thus, she is first a daughter, next a wife and a mother, never an independent person in her own right. A daughter is normally an unmitigated expense, someone who will never contribute the family income and who upon marriage will take away a considerable part of her family's fortune as her dowry. This cultural devaluation of women has heightened their feelings of worthlessness and inferiority.

Liberal feminists considered law as an instrument of social change and reform. They believed that through affirmative action, women could be given equal rights. While radical feminists highlight the role of law as an instrument of oppression in the patriarchal India social system, the contemporary women's movement continues to fight for law reforms and substantial equality.

In India, the gender relations are understandable more in terms of culture of hierarchy than that of inequality. Some of the notable mechanisms of culture of gender hierarchy in India are the norms of son preference, daughter is meant for the other family (Kanya to paraya Dhan), Parental obligations to marry off the daughter (Kanyadaan), 'Sati' as the ideal of wife's fidelity to husband (Pativrita), motherhood as the measure of womanhood (Matritva). All these norms are distinctive to the cultural psyche of gender relations in India.

Liberal feminists considered law as an instrument of social change and reform. They believed that through affirmative action, women could be given equal rights. While radical feminists highlight the role of law as an instrument of oppression in the patriarchal India social system, the contemporary women's movement continues to fight for law reforms and substantial equality. Legislative victories have been won but women continue to suffer oppression and law continues to shape and sustain unequal power relations.

In the post independent period, the concern for women evolved through three phases: welfare, development and empowerment. Under the welfarist approach, the focus was on providing primary health care facilities like: maternity and nutrition but in 6th Five Year Plan, (1980-85), there was a shift from welfare to development as 6th plan has a full chapter on 'Women and Development' (WAD). And then the focus was laid on the question of empowerment. A number of acts have been enacted to provide for empowerment of women. Various strategies have been devised to change the culture of gender hierarchy which still has considerable hold over the common man.

The National Committee on the Status of Women in India, (1974) in its report, held that the women are not conscious partners in the processes of Social change. It also pointed to the increasing withdrawal of women from the labour force and productive activites. This has made the girl in her father's family a liability rather than an asset. They are unequal, powerless and vastly exploited. The year 2001 was observed the year of women empowerment. But still, according to 2011 census report, 65.46% of Indian women are literate and there are only 940 women to

every 1000 men. Women remain more or less in periphery of the political arena

Now, when we have entered in post-modern world where we call ourselves as technocrats, industrialized, globalised and learned society. In this present era in India, women are excelling in every walk of life like: Military, Medicine, IT, Academics, Politics, Law, etc. but if their participation is compared to the male folk of the country, the percentage will be disheartening. It is unfortunate that even today when we have entered in 21st century, our successive governments are making efforts to make people aware over the women related issues through various schemes like: Save the girl Child, Beti Bachao Beti Padhao, Jannani Suraksha Yojna, and many others. Thus, the question arises here that 'Is women really empowered in India? The answer to this question is 'No'.

The process of Women Empowerment in India is still seems to a far distant dream. By mere economic independence of women or by increasing women's participation in work force do not empower them in true sense. The economic empowerment of women would certainly help for the social upliftment of women but empowerment is a broader concept.

Very recently in India, a landmark judgement came on Triple Talaq which is a welcoming step in favour of women in the largest democratic country like India. There are many more such issues which are prevailing in India, hence, there is a strong urge of a Uniform Civil code and other such reforms.

It is our moral, social and constitutional responsibility to ensure their progress by providing them with equal rights and opportunities. Legislation can not by itself solve the deep rooted social problems. One has to approach them in other ways too, but legislation is necessary and essential, so that it may give that push and have the educative factor as well as the legal sanctions behind which help public opinion to be framed and given a certain shape.

Conclusion: A Gender perspective is the need of the hour, which could cover human question and take in to account the needs and interest of both the genders and integrate them to work for human betterment. Such a model of complementary roles and harmonious coexistence would provide a saner and better paradigm than the western feminist approach rooted in gender conflict, male supremacy and female oppression. Attitudinal change is needed both in men and women. Men cannot realise their full potential as long as women are prevented from achieving theirs. Empowering women must be a united approach, a cause that requires continued attention and stewardship by all. We need to augment our efforts for empowering women and enhance their progress. Men and women working together in all realms of human existence can result in a harmonious, non-repressive society and a better world in the future. ■

(Auther is Assistant Professor in Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का मार्च 2018 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता, महिला सशक्तीकरण जैसे महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

पटना विश्वविद्यालय समेत बिहार के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय में लहराया भगवा

बिहार की राजनीति का केन्द्र माने जाने वाले पटना विश्वविद्यालय व जयप्रकाश विश्वविद्यालय समेत वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने शानदार जीत हासिल की है। बता दें कि हाल में संपन्न बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के विश्वविद्यालयीन छात्रसंघ चुनाव में भी विद्यार्थी परिषद् ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी।

बिहार में संपन्न छात्रसंघ चुनाव में विजय हासिल करने के बाद अभाविप के क्षेत्रीय संगठन निखिल रंजन ने कहा कि यह तो केवल झांकी है पूरे प्रदेश में भगवा लहराना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में विभाजन की राजनीति करने वाले छात्र संगठनों को छात्रों ने नकार कर विद्यार्थी परिषद् के ऊपर विश्वास किया है, जो छात्रों के प्रति विद्यार्थी परिषद् के समर्पण को दर्शाता है।

बिहार की राजधानी में पटना विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने पांच में से तीन सीटों पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में अभाविप के उम्मीदवारों में केन्द्रीय पैनल में उपाध्यक्ष अभाविप की महिला प्रत्याशी योशिता पटवर्धन और महासचिव पद पर अभाविप के सुधांशु झा ने जीत हासिल की है। इसके अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद पर भी अभाविप प्रत्याशी नीतीश कुमार ने जीत का परचम लहराया है। वहीं वाम संगठनों को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

छपरा स्थित **जयप्रकाश विश्वविद्यालय** में 25 साल बाद संपन्न हुए छात्र संघ (केन्द्रीय पैनल) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने अपने प्रतिद्वंदी छात्र संगठनों के गठबंधन को अध्यक्ष समेत सभी पदों पर पराजित कर दिया है। विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रजनीकांत सिंह ने गठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी कुमारी को तीन मतों से हरा कर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। 39 में रजनीकांत को 21 एवं रोहिणी को 18 मत मिले।इसी प्रकार विद्यार्थी परिषद के विजय प्रकाश ने उपाध्यक्ष पद पर गठबंधन के चंदन कुमार को, महासचिव पद पर रंजीत कुमार ने अर्पित राज को, संयुक्त सचिव पद

पर शशि कुमार पांडेय ने राजेश रंजन एवं कोषाध्यक्ष पद पर विद्यार्थी परिषद के शाहिल राज ने छात्र जदयू के मोनू कुमार को पराजित कर सेंट्रल पैनल के सभी पदों पर कब्जा जमा लिया। ज्ञात हो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सेंट्रल पैनल के चुनाव में छपरा, सिवान एवं गोपालगंज में कुल 40 काउंसिल मेंबर विभिन्न कॉलेजों से चुनाव जीत कर आए थे। महाविद्यालयों से निर्वाचित इन काउंसिल मेंबर ने ही विश्वविद्यालय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए वोट किया हैं जिसमें अभाविप ने सभी पदों पर जीत हासिल की है।

वहीं **आरा** स्थित **वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय** में हुए छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल में अभाविप ने क्लीन स्वीप किया है। अभाविप के प्रत्याशियों ने छात्रसंघ चुनाव में सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अभाविप के अमित कुमार सिंह जीते जबकि उपाध्यक्ष पद पर अभाविप की सोनाली कुमारी विजयी घोषित की गईं। विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष के तौर पर परिषद् के ही संटू मित्रा ने चुनाव जीता जबकि संयुक्त सचिव के पद पर परिषद् के गणेश दत्त तिवारी और महासचिव के तौर पर परिषद् की अन्नू कुमारी चुनाव जीतने में सफल रहीं। चुनाव में कुल 105 में से 103 महाविद्यालय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नागपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में भी अभाविप की जीत

नागपुर विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। विश्वविद्यालय के कार्यालय पदाधिकारियों के दोनों पदो पर परिषद् ने जीत हासिल की है। आशीष मोहिते और आकाश को क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव चुना गया है। जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक साकेत बहुगुणा ने कहा कि यह जीत विद्यार्थी परिषद् के द्वारा साल भर छात्र हित के लिए किये जा रहे संघर्षों का परिणाम है। जीत के बाद अभाविप के कार्यकर्ता दोगुने उत्साह के साथ परिसर में काम करेंगे। ■

भगिनी निवेदिता का योगदान अविस्मरणीय : खंडेलवाल

भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श मूल्यों को आत्मसात कर जन चेतना जगाने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में उपेक्षा का शिकार रहे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के शोध कार्यों को पाश्चात्य जगत में पहचान व सम्मान दिलाने में भगिनी निवेदिता ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने डॉ. बसु की वैज्ञानिक सहायक के रूप में उनके शोध पत्रों का लेखन किया तथा विश्व में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान से परिचित करवाया। भारतीय संस्कृति के प्रति भगिनी निवेदिता का योगदान अविस्मरणीय है। ये बातें अभाविप द्वारा दमण में आयोजित भगिनी निवेदिता सार्धशती समारोह में अभाविप के विशेष क्षेत्र संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कहीं।

दसअसल अभाविप द्वारा देश भर में भगिनी निवेदिता सार्धशती समारोह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के प्रति भगिनी निवेदिता के योगदान

को जन-जन तक पहुंचाना है। संगोष्ठी का आयोजन दमण एवं वापी के विभिन्न महाविद्यालयों में किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने सहभाग लिया। ■

महिला सशक्तीकरण और अभाविप

| सुश्री ममता यादव |

9 जुलाई 1949 को जब अभाविप की शुरूआत हुई तब उस समय के कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा था युवा भारत - यशस्वी भारत का, वह आज साकार होता दिखाई दे रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था - महिलाओं को शिक्षित करो, अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं ढूंढ लेंगी। प्रा. यशवंतराव केलकर ने कहा था - छात्राओं को पारिवारिक वातावरण प्रदान करो, कार्य करने का अवसर दो निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता बढाओ वे स्वयंसिद्धा बनेंगी और आज उनकी एक-एक बात सत्य सिद्ध होती दिखाई दे रही है। अभाविप में छात्रा सहभाग प्रत्येक स्तर पर दिखाई दे रहा है।

मार्च माह में सहज ही महिला सम्मान, सशक्तीकरण, महिला चिंतन, महिला विमर्श संबंधी विषयों पर कार्यक्रमों की संख्या तथा महिला विषयों पर लेख, संगोष्ठी आदि का आयोजन बाकी महीनों से अधिक दिखाई देता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि अंतर - राष्ट्रीय स्तर पर आठ मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक दिन - प्रतिदिन के सहभाग को कार्यक्रमों के रूप में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का भी यह दिन है।

अभाविप में छात्रा सहभाग यह आग्रह का विषय है। यहां कोई प्रतिशत तय नहीं, यह तो सहज स्वाभाविक रूप से समाज व राष्ट्र कार्य में छात्रा आगे आये दायित्व लेकर कार्य करें, इस हेतु अनुकूल वातावरण और अवसर प्रदान करने हेतु संगठन प्रयास करता है। इसी का परिणाम दिखाई देता है कि आज कुल सदस्यता में लगभग 35 प्रतिशत छात्रायें हैं।

अभाविप के संविधान में ही वर्णित है कि विद्यार्थियों

का संगठन है जिसमें छात्र - छात्राएं मिलकर कार्य करेंगे। हमने अपने कार्यों द्वारा यह स्थापित किया है कि संगठन में कोई प्रथम या दोयम दर्जे पर नहीं अपितु सभी समान है, सभी को कार्य करने का अवसर है, सभी को अनुकूलता है कि एक परिवार भाव है जो छात्र - छात्राओं को प्रेरणा देता है राष्ट्रपुनर्निर्माण में अपना जीवन लगाने की।

9 जुलाई 1949 को जब अभाविप की शुरूआत हुई तब उस समय के कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा था युवा भारत - यशस्वी भारत का, वह आज साकार होता दिखाई दे रहा है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था -

महिलाओं को शिक्षित करो, अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं ढूंढ लेंगी।

प्रा. यशवंतराव केलकर ने कहा था -

छात्राओं को पारिवारिक वातावरण प्रदान करो, कार्य करने का अवसर दो निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता बढाओ वे स्वयंसिद्धा बनेंगी और आज उनकी एक-एक बात सत्य सिद्ध होती दिखाई दे रही है। अभाविप में छात्रा सहभाग प्रत्येक स्तर पर दिखाई दे रहा है।

रचनात्मक कार्यक्रम हो या आंदोलन, छात्रसंघ चुनाव हो या बौद्धिक विमर्श, प्रत्येक क्षेत्र में छात्राओं ने अपनी सक्रिय सहभागिता दिखाई है।

आज महाविद्यालय /विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में बड़ी संख्या में छात्राओं ने जीत दर्ज की है। परिसर के अंदर व बाहर शिक्षा क्षेत्र में आई विसंगतियों को दूर करने व अन्य सामाजिक मुद्दों पर हुए आंदोलनों में लाठियां खाने से भी पीछे नहीं हटी हैं।

अभाविप में जिस प्रकार से छात्राओं का सहभाग बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण यहां पारिवारिक वातावरण और लगातार मिलने वाला मोटीवेशन है। आज राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनेक प्रांतों में प्रदेश मंत्री, सह मंत्री, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य से लेकर अनेक प्रमुख दायित्वों का निर्वहन जिस प्रकार से छात्रायें कर रही हैं, वह यह स्पष्ट करता है कि कैसे संगठन में उनको गढ़ा है। निर्णय प्रक्रिया में छात्राओं की सक्रिय सहभागिता से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अपने जीवन का कुछ अमूल्य, समय संगठन को देते हुए राष्ट्र कार्य में लगाने की प्रेरणा से लगातार पूर्णकालिक/विस्तारक के रूप में कार्य करना। मा. गीताताई गुंडे जिन्होंने अभाविप में पूर्णकालिक के रूप में अपने जीवन के अधिकतम वर्ष लगा दिये उनकी प्रेरणा से ही आज 94 छात्रा विस्तारक/पूर्णकालिक के रूप में संगठन कार्य कर रही हैं। यह किसी भी समाज व संगठन के लिए एक आदर्श स्थिति हो सकती है जहां संगठन पर परिवार व समाज का इतना विश्वास स्थापित हो जाये कि अपनी बेटियों को सहर्ष राष्ट्रकार्य के लिए अग्रसर कर दें। भगिनी निवेदिता सार्धशती के अवसर पर संकल्पित सभी छात्राओं को साधुवाद। छात्रा सम्मेलन, व्यक्तित्व विकास शिविर (पीडीसी), संगोष्ठी, छात्रा संसद जैसे अनगिनत ऐतिहासिक कार्यक्रमों में सहभाग से लेकर छात्रा सहभाग की यह छात्रा नये मुकाम तक पहुंच रही है। गत माह दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं के विषय को लेकर विशेषतः उनकी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए एक मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं की हिस्सेदारी हुई। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। छात्राओं के शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान व स्वालंबन से जुड़े सभी विषयों को मुखर होकर उठाने का कार्य अभाविप कार्यकर्ताओं ने किया है।

छात्राओं के सामाजिक कार्य में सहभाग का एक विशेष उदाहरण मिशन साहसी के रूप में दिखाई देता है। मुंबई में दो फरवरी से प्रारंभ हुए आत्मरक्षा शिविरों में लगभग 10,000 छात्राओं ने पांच कैम्पों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण इन छात्राओं द्वारा छह मार्च को मुंबई के बीकेडी ग्राउंड में आत्मरक्षा(Self Defence) का प्रात्याक्षिक किया गया।

"मिशन साहसी" एक पहल है छात्राओं को निडर, सबल, सशक्त, आत्मविश्वासी बनाने की...। यह पहल है स्वयं को किसी भी दुष्कर स्थिति में सुरक्षित रखने की। यह पहल है स्वाभिमान व सम्मान से जीने के अधिकार की। जब समाज के अन्य लोग सरकार/पुलिस/प्रशासन से अपेक्षा रखते हुए समस्या पैदा होने के बाद समाधान के प्रयास करते हैं वहीं मिशन साहसी पहल है समस्या को पैदा ही ना होने देने की।

अभाविप की कार्यकर्ता लगातार नये इतिहास रच रही हैं। आनेवाले समय में छात्राओं का सहभाग राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य में निरंतर बढ़ता रहेगा ऐसी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। ■

(लेखिका अभाविप की अ. भा. छात्रा कार्य प्रमुख हैं।)

अभाविप द्वारा आयोजित निशुल्क शिक्षा शिविर से गरीब छात्रों के उम्मीदों की लगे पंख

दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अभाविप ने उम्मीदों का पंख दिया है। अभाविप, कोटा के द्वारा गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया ताकि छात्र बेहतर कोचिंग लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या में निजी एवं सरकारी विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। शिविर में पहुंचे माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक रामस्वरूप मीणा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् ने हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर अपना दायित्व निभाया है। उन्होंने कहा अभाविप की यह पहल सराहनीय है, शिक्षा विभाग इसमें सहयोग करेगा। वहीं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र गहलोत ने कहा कि कोटा को कोचिंग नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है जहां बिना खर्च विद्यार्थी को संबल मिल सके। इस स्थिति में यह पहल रंग दिखाएगी व आर्थिक रूप से तंग बच्चों के सपने भी साकार होंगे।

गौरतलब है कि अभाविप के द्वारा समय - समय पर

देश भर के विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क शिक्षा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। अभाविप की मानें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से मोटी राशि खर्च कर कोचिंग नहीं कर सकते, ये बच्चे बिना किसी खर्च के कोचिंग कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग शुरू की गई है। बता दें कि इस शिक्षा शिविर में केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि आईआईटीयन, रिटार्यड कर्नल, डॉक्टर भी पढ़ा रहे हैं। ■

अभाविप की मांगों के आगे झुकी महबूबा सरकार, यूआईईटी के फैसले को लिया वापस

जम्मू - कश्मीर सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (यूआईईटी) से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीसीईटी) में शिफ्ट करने पर अभाविप ने कड़ा विरोध किया। अभाविप के आंदोलन के सामने सरकार ने अपना फैसला पलट कर यूआईईटी को पुनः बहाल किया।

सरकार के फैसले के विरूद्ध अभाविप ने आठ फरवरी 2018 क्रमशः हस्ताक्षर अभियान, विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, धरना आदि शुरू किया, लेकिन सरकार इससे भी नहीं डिगी तब मजबूर होकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गये। भूख हड़ताल के 10 वें दिन अभाविप ने राज्य के शिक्षा मंत्री का घेराव किया। इस दौरान पुलिस द्वारा छात्र - छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसायी गई, जिसमें ग्यारह कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक की गई कार्रवाई के कारण छात्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गये। आंदोलन को बढ़ता देख शिक्षा मंत्री घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे और यूआईईटी को वापस जम्मू विश्वविद्यालय के अधीन करने की घोषणा की एवं छात्रों से आग्रह किया कि वे अपना आंदोलन को समाप्त करें। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद अभाविप ने अपना आंदोलन समाप्त किया। यूआईईटी को वापस जम्मू विश्वविद्यालय में शामिल करने की फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए प्रांत संगठन मंत्री जीत सिंह ने कहा यह छात्रों के संघर्ष की जीत है। ■

75 फीसदी अनिवार्य उपस्थिति पर विरोध कितना सही?

देश भर के कई विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। 75 फीसद अनिवार्य उपस्थिति के बाद छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। केवल छात्र ही नहीं बल्कि कई जगह शिक्षक भी इसके विरोध में हैं। ताजा विरोध विवादों के लिए चर्चित जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में हो रहा है। इस बार विवाद का विषय है "कक्षाओं में अनिवार्य उपस्थिति"। जे.एन.यू. की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि बीए, एमए, एमएससी, एमटेक, पीजी डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी और सभी अंशकालिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को सेमेस्टर के अंत की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विश्वविद्यालय कुलपति का यह कहना है कि अगर कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई तो इससे अकादमिक प्रदर्शन और बेहतर होगा। परन्तु जे.एन.यू .के छात्र और शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं , उनका यह तर्क है कि कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य करने से छात्र दबाव में आएगे और जेएनयू में छात्र अपनी कक्षाएं नहीं लेते या ज्यादा लेते हैं, यह बड़ी समस्या नहीं है। जेएनयू में अगर कोई कमी है तो वह है छात्रावासों में सुविधाओं की कमी, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, किताबों व संसाधनों की कमी है। प्रश्न यह उठता है कि देश की सर्वश्रेष्ठ आधारभूत सुविधाओं– भवन, छात्रावास, पुस्तकालय के साथ शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात के बावजूद क्या जेएनयू विश्व की चुनिंदा शैक्षिक संस्थाओं के आसपास भी कहीं पहुंचता है ? जे. एन. यू. से शुरू हुआ यह विरोध धीरे धीरे अन्य विश्वविद्यालयों में भी पांव पसार रहा है। शिक्षकों को भी अनिवार्य उपस्थिति से आपत्ति है क्योंकि छात्रों की उपस्थिति से शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी इसीलिए इस 75 फीसद उपस्थिति के विरोध में शिक्षकों और छात्रों की जुगलबंदी है।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने अनिवार्य उपस्थिति के विषय को लेकर देश भर के आम छात्रों और शिक्षकों से चर्चा की, प्रस्तुत हैं उनके विचार –

वर्ग में पढाई के अलावा भी छात्र कई अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं । खेलकूद, वाद विवाद तथा अन्य कई सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं। यदि सशरीर उपस्थिति के चक्कर में किसी छात्र की कोई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि प्रभावित हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया हैं इसे जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता ।

- **डा0 विमिलेश शाह ,** एसोसिएट प्रोफेसर (भोपाल)

छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य करनी चाहिए। आज जो लोग पढना नहीं चाहते वहि कुतर्कों से बातों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जब क्लास अटेंड ही नहीं करनी है तो फिर रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ही क्यों लेते हैं ? डिस्टेंस में पढाई करने का विकल्प ऐसे लोगों के लिए खुला हुआ है। लेकिन कक्षा का बहिष्कार करके यह सिद्ध करना कि इससे छात्रों का नुकसान होगा यह बिलकुल भी सही नहीं है।

- **थॉमस मैथ्यू ,** शिक्षक (मुंबई)

कक्षाएं नियमित हो, शिक्षक समय पर आये और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाये तो छात्र खुद ब खुद कक्षाओं की ओर उन्मुख होंगे। पढने के लिए छात्रों पर दबाव बनाना यह किसी भी स्थिति में सही नहीं है । कई छात्र आजकल लाइब्रेरी में भी अध्ययन करते हैं और कई सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से पढाई करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षाओं में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना सम्भव नहीं है ।

- **सत्या रानी,** एम०फिल० छात्रा (दिल्ली वि०वि०)

छात्रों के लिए उपस्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, खासकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में...क्योंकि यहां पर गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा जैसे दूर - दूराज से छात्र सिर्फ हस्ताक्षर के लिए विश्वविद्यालय आते हैं। चूंकि एम.फिल एवं पीएचडी के छात्रों के लिए कोई कक्षा आयोजित नहीं होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए शिक्षण मांगा जाता है और दूसरी तरफ हमारे विश्वविद्यालय में छात्र उपस्थित रहने के लिए बाध्य करता है, ऐसी स्थिति में छात्र महाविद्यालय पढ़ाये या उपस्थिति दिखाने के लिए विश्वविद्यालय जाये। आईआईटी जैसे संस्थानों में अनिर्वाय उपस्थिति में ढ़ील दी जा रही है ताकि शोध छात्र अच्छे से अपना शोध कार्य पूरा कर सके। अनिर्वाय उपस्थित के बजाय सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को डिजिटल क्लास की ओर ध्यान देना चाहिए।

- **निधि त्रिपाठी,** शोध छात्रा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली।

कक्षाओं का बहिष्कार यदि छात्र करें तो यह समझ में आता है कि वो अबोध हैं या किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं , परन्तु यदि शिक्षक भी उनके साथ कंधे से कन्धा मिलाकर 75 प्रतिशत उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दरअसल शिक्षक को नियमित आना पड़ता है तो यह उसे रास नहीं आता। मासिक वेतन में एक प्रतिशत कटौती भी बर्दाश्त नहीं लेकिन कक्षाओं के बहिष्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते है।

- **बादल कुमार ठाकुर ,** स्कूल ऑफ़ आर्काइवल स्टडीज

विश्वविद्यालयों द्वारा 75 फीसदी अनिवार्य उपस्थिति को लागू करना स्वागत योग्य कदम है। अनिवार्य उपस्थिति होने पर शिक्षक वर्ग में पढ़ाने आयेंगे, छात्रों में पढ़ाई के प्रति रोचकता बढ़ेगी। जब तक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में अनुशासन बहाल नहीं होगा तब तक शिक्षा के हालत में सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 75 फीसदी अनिवार्यता पर विवाद बेबुनियाद है, छात्र कक्षा में नहीं जायेगें तो पढ़ाई के लिए कहां जाएंगे? छात्रों को विरोध करने के बजाय शिक्षकों पर दबाव बनायें ताकि वे नियमित रूप से कक्षा में आकर पढ़ायें।

- **विवेक शर्मा,** छात्र बीए. अंतिम वर्ष (उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलिगुड़ी)

पचहतर फीसदी उपस्थिति निश्चित रूप से अनिवार्य होना चाहिए। उपस्थति अनिवार्य नहीं होने के कारण छात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से कटते जा रहे हैं, जिस कारण उसके अंदर क्रियेटिविटी मर रही है। कक्षा में नियमित रूप से आने पर छात्रों की कौशल क्षमता का विकास होगा। मैं खुःद एक शोध छात्रा हूं, कक्षा में आने के बाद मेरे अंदर की खोजी प्रवृति में बढ़ोत्तरी हो रही है और मेरी रचनात्मकता में काफी विकास हुआ। शिक्षक अगर नियमित रूप से कक्षा में छात्रों को पढ़ायेंगे तो उनके अंदर भी नयापन आयेगा और पढ़ाने के प्रति उनकी अभिरूचि बढ़ेगी। छात्रों की अनुपस्थिति लगातार गिरने के कारण उच्च शिक्षा का खस्ता हाल है।

- **प्रनति,** शोधार्थी (सेंटर फॉर इकोनोमिक्स एंड सोशल स्टडीज, आईसीएसएसआर हैदराबाद)

छात्रसंघ चुनाव

पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में जीत के बाद विजयी मुद्रा में नवनिर्वाचित छात्र नेता

नागपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने के बाद विजय जुलूस निकालते अभाविप कार्यकर्ता

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 March, 2018
Date of Publishing: 8 March, 2018

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

मिशन साहसी